फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 232 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 27 मार्च, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

The Four Temperaments Yourself, Your Team...

Imagine a startup CEO who has a Sanguine temperament. She would likely be a magnet for investors and employees alike, energizing the company with lively town halls and creative brainstorming sessions...

Sunday afternoon on the island of La Grande Jatte

दो दिन बचे हैं, ''डैड लाइन'' पूरी होने में

कांग्रेस बदहवास सी दिख रही है, अकबर रोड स्थित मुख्यालय को बचाने के प्रयास में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यालय रहे 24, अकबर रोड को खाली करने के लिए अंतिम नोटिस दिए जाने के बाद, पार्टी अपने इस परिसर को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने बैक-चैनल कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए सरकार के उन लोगों से मीटिंग करने की कोशिश की है, जो मदद कर सकते हैं, लेकिन अब तक सभी प्रयास विफल रहे हैं और सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है।

यह स्पष्ट रूप से शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर हो रहा है। इसके साथ ही, युवा कांग्रेस कार्यालय 5 रायसीना रोड और जवाहर भवन को भी खाली करने के लिए कहा गया है।

यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राजनीतिक दलों से, लुटियंस दिल्ली के बाहर स्थानांतरित करने को कहा गया था, क्योंकि यहां ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याएं हो रही थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था और यूपीए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को जमीन आवंटित की थी।

पिछले नवंबर में कांग्रेस ने अपने नए पार्टी कार्यालय ''इंदिरा भवन'' का उद्घाटन किया, लेकिन पार्टी 24 अकबर रोड को किसी कांग्रेस सांसद के नाम पर आवंटित करवाने में पूर्णतया विफल रहीं।

यह भवन कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही आवंटित रहा। इन मुद्दों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस ने ''बैक चैनल डिप्लोमैसी'' के मार्फत भाजपा नेताओं से बातचीत भी की, पर, सब जगह उनके प्रयास निष्फल हुए।
- यह समस्या खड़ी ही नहीं होती, अगर, कांग्रेस ने 24, अकबर रोड स्थित बंगले को अपने किसी सांसद के नाम ''अलॉट'' करा लिया होता, पर, बंगला औपचारिक तौर पर, कांग्रेस पार्टी को आवंटित दिखाया जाता रहा।
- एआईसीसी में प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाले लोगों की यह जिम्मेवारी थी, पर, लगता है पूरी व्यवस्था ही खत्म हो गई है। अतः, अब बदहवास सी स्थिति दिख रही है, पार्टी में, क्योंकि कोर्ट की शरण में जाने के विकल्प में कुछ दम नहीं लगता, क्योंकि, भूमि आवंटित करके, पार्टी को मुख्यालय के निर्माण के लिए पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है।
- जैसा कि विदित ही है, यूपीए सरकार के शासनकाल में, सुप्रीम कोर्ट ने रोजमर्रा ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से निपटने के लिए फैसला सुनाया था कि लुटियंस एरिया से सभी राजनीतिक पार्टियों को बाहर शिफ्ट करवा देना चाहिए तथा सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को भूमि भी आवंटित कर दी थी, नया मुख्यालय बनाने के लिए।

ईरान वॉर के कारण महंगी हुई स्वास्थ्य सेवाएं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। सभी क्षेत्रों की तरह भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र भी ईरान में चल रहे युद्ध के अप्रत्यक्ष प्रभावों को महसूस करने लगा है। हालांकि अभी तक नियमित चिकित्सा सेवाओं में कोई बडा व्यवधान नहीं आया है, लेकिन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने से सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे शिपिंग मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहे, तो इसका असर अंततः मरीजों की जेब पर पड़ेगा।

भारत के मेडिकल डिवाइस और फार्मा सेक्टर बड़ी मात्रा में कच्चा माल, सक्रिय औषधीय तत्व (एपीएल) और विशेष घटक (कम्पोनेन्ट्स) आयात करते हैं, जिनमें प्लास्टिक और इन्टरमीडिएट केमिकल शामिल हैं। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में हो रही देरी, बढ़ी हुई ढुलाई लागत और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य कंपनियों की लागत बढ़ रही है। सिरिंज, ग्लव्स, कैथेटर और अन्य कन्ज्यूमेबल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत के बड़े पैमाने पर चिकित्सकीय उपकरण, दवाओं के घटक आदि आयात होते हैं। इस समय ईरान वॉर के कारण माल आना मुश्किल हो गया है।

भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल, जिन्हें ईरान अपना मित्र मानता है

इन देशों की सूची में भारत के साथ चीन, रूस, ईराक, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में, ईरान ने कहा है कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज़ स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) भारत के लिए खुला रहेगा। यह जलमार्ग, जो फारस की खाड़ी का संकरा मुहाना है और जिसके माध्यम से सामान्यतः दुनिया के पाँचवें हिस्से का तेल भेजा जाता है, पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के बाद से ईरान के नियंत्रण में है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान के सरकारी टीवी से बातचीत में स्पष्ट किया कि, पश्चिमी मीडिया के दावों के विपरीत, यह स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने कहा, ''कई जहाज मालिकों, या उन देशों ने, जो इन जहाजों के मालिक हैं, हमसे संपर्क किया है और स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इनमें से कुछ देशों को मित्रता के लिए तथा कुछ को अन्य कारणों से हमने सुरक्षित मार्ग देने का विचार किया है। हमारी सेनाओं ने उन्हें रास्ता दिया है। उन्होंने आगे कहा, ''आपने खबरों में देखा होगा: चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत। कुछ रात पहले उनके दो जहाज यहां से गुज़रे, और कुछ अन्य देश, यहाँ तक कि मुझे लगता है बांग्लादेश भी। ये वे देश हैं, जिन्होंने हमसे बात की और हमारे साथ तालमेल किया, और यह भविष्य में भी, युद्ध के बाद भी, जारी रहेगा।

- ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से इन देशों के जहाजों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
- ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान के सरकारी टीवी पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की यह खबर झूठी है, हमने होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह बंद किया है। जिन देशों को हम मित्र मानते हैं, उन्हें हमने सुरक्षित रास्ता दिया है।
- अराघची ने कहा, आपने खबरों में देखा होगा, दो दिन पहले भारत के दो जहाज होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरे थे।

होर्मुज़ स्ट्रेट के पास 1900 जहाज फंसे हैं

लंदन/तेहरान, 26 मार्च। पश्चिम एशिया में पिछले 27 दिनों से जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में, मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में, लगभग 1,900 व्यापारिक जहाज फंसे हुए हैं। युद्ध शुरु होने के बाद होर्मुज में समुद्री यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कतर से गैस आयात घटाना भारत के लिए वरदान बना

भारत ने 2014 के बाद से कतर से गैस आयात घटाना शुरु कर दिया था, इससे पूर्व भारत कुल गैस उपभोग का 86 प्रतिशत कतर से मंगाता था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। 19 मार्च को क़तर के रास लफ़ान हाइड्रोकार्बन कॉम्प्लेक्स पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि क़तर दुनिया की लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) के लगभग पाँचवें हिस्से की आपूर्ति करता है। यह चिंता भारत में विशेष रूप से गंभीर थी, क्योंकि हमारी जरुरत की एलएनजी का 40 प्रतिशत क़तर से आता है।

इस कॉम्प्लेक्स के अनिश्चितकाल के लिए बंद होने और होर्मुज़ स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद करने की स्थिति में, क़तर की गैस पर भारत की निर्भरता घातक लग सकती है। ऐसा है, लेकिन केवल बहुत कम समय के लिए। ऐतिहासिक आयात आंकड़े बताते हैं कि एक दशक पहले भारत की निर्भरता इससे कहीं अधिक थी; लेकिन 2014 के बाद भारत सरकार ने क़तर की गैस पर निर्भरता कम करने के लिए एक सुविचारित रणनीति शुरू की। यह इस बात का उदाहरण है कि दूरदृष्टि को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ज्ञातव्य है कि 19 मार्च को ईरान के हमले में कतर का सबसे बड़ा, रास लाफान हाइड्रोकार्बन्स कॉम्पलैक्स ध्वस्त हो गया और यह अगले कुछ माह तक बंद रहेगा। अगर भारत सिर्फ कतर पर ही निर्भर रहता तो भारी दिक्कत में पड़ सकता था।
- सन् 2014 में मोदी सरकार ने कतर पर गैस निर्भरता घटानी शुरु की, जो 86 प्रतिशत से घट कर 39 प्रतिशत रह गई है।
- इस समय भारत कतर के अलावा नाइजीरिया, इक्वटोरियल गिनी, ऑस्ट्रेलिया और ओमान से गैस ले रहा है।

राजस्थान का कॉमर्शियल गैस आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ा

जयपुर, 26 मार्च। प्रदेश में आवश्यक ईंधन आपूर्ति को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केन्द्र सरकार ने राजस्थान को अतिरिक्त कमर्शियल गैस का आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केन्द्र से अतिरिक्त आवंटन की मांग की थी, जिस पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीज़ल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रधानमंत्री का आभार जताया।

इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड के नौसेना कमांडर अलीरेज़ा तंगसीरी, इज़रायली बमबारी में मारे गए

तंगसीरी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से आवागमन बंद करने के प्लान के रचयिता थे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के नौसैनिक कमांडर अलीरेज़ा तंगसीरी की बंदर अब्बास के तटीय क्षेत्र में अमेरिका-इज़रायल के हमले में मौत हो गई है। इज़रायली मीडिया ने एक इज़रायली अधिकारी के हवाले से यह खबर दी। टाइम्स ऑफ इज़रायल की रिपोर्ट के अनुसार, तंगसीरी होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कराने के लिए जिम्मेदार थे।

इज़रायली मीडिया का दावा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट बिना किसी अतिरिक्त नाकाबंदी के खुल गया है।

इस हमले पर अभी तक ईरान या इज़रायली सेना की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। यदि इसकी पुष्टि होती है, तो यह अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुके युद्ध में एक और बड़ा नुकसान होगा।

तंगसीरी उन कुछ बड़े नामों में शामिल थे, जो अब तक अमेरिका-इज़रायल के हत्या प्रयासों से बचते रहे थे। सन् 2018 से इस पद पर रहे एक अनुभवी कमांडर के रूप में उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

फारस की खाड़ी से खुले समुद्र की ओर जाने वाले इस रणनीतिक मार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण रखते हुए, ईरान उन जहाजों को रोक रहा था, जिन्हें वह अमेरिका और इज़राइल के युद्ध प्रयासों से जुड़ा मानता है, जबकि कुछ अन्य जहाजों को सीमित रूप से गुजरने दे रहा था। सामान्य समय में, दुनिया भर में बेचे जाने वाले कुल तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है।

तेहरान द्वारा इस मार्ग पर लगाए गए नियंत्रण के कारण इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से ऊर्जा की दैनिक शिपिंग में 95 प्रतिशत की गिरावट आई है। शिपिंग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, अभी तक ईरान या इज़रायल ने इस बमबारी की खबर की पुष्टि नहीं की है।
- अगर, इस बमबारी में तंगसीरी की मृत्यु की पुष्टि हो गई तो तंगसीरी का नाम उन चुनिंदा नामों में अव्वल नम्बर पर होगा, अब तक जिन्हें अमेरिका-इज़रायल बमबारी नहीं मार पाई थी।
- तंगसीरी 2018 से अपने इस पद पर विराजमान थे, जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाजों के आवागमन को प्रतिबंधित किया था।